statement is laid on the Table of the Sabha. [Placed in Library. See No. LT-1175/67].

महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने

*1364. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री देवराव पाटिल :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री श्रीधरन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 1 जुलाई, 1967 से महाराष्ट्र के चीनी के कारखानो ने सरकार को चीनी बेचना बन्द कर दिया है,

(ख) यदि हा तो इस के क्या कारण है; और

(ग) इस मामले मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र के सहकारी कारखानों ने 2 जुलाई, 1967 को अर्थात् 28 जून 1967 को उत्तरी भारत के कारखानो के निकासी मूल्यो में संशोधन करने के तुरन्त बाद चीनी देना बन्द कर दिया था। उन्होने इच्छा व्यक्त की कि जब तक उन के निकासी मूल्यों में भी वृद्धि नही की जाती तब तक वे चीनी नही देंगे। तब महाराष्ट्र के चीनी कारखानों के निकासी मूल्यों में परिसंशोधन नही किया जा सकता था क्योंकि इन कारखानो के कार्यचालन के अन्तिम परिणाम समय पर नही मिले थे। महाराष्ट्र के कारखानो के निकासी मूल्य 14 जुलाई, 1967 से परिशोधित किये गये थे और सहकारी कारखानो ने चीनी देने का निर्णय किया है।

खाद्यान्नों का समाहार

*1365 श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने हाल मे किन दरो पर खाद्यान्न खरीदा ;

(ख) सरकार का विचार इस खाद्यान्न को किन दरो पर बेचने का है;

(ग) अब तक कितने खाद्यान्न का समाहार किया गया है तथा कितना खाद्यान्न खरीदने का प्रस्ताव है, और

(घ) समाहार किये गये खाद्यान्न की बिक्री कब आरम्भ होगी और यह कितने समय तक दिया जाता रहेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारो ने जिन मूल्यों पर खाद्यान्न अधिप्राप्त किए हैं, वे एक जैसे हैं। विभिन्न

खाद्यान्नों के भिन्न भिन्न-मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) केन्द्रीय भण्डार से दिये जाने वाले खाद्यान्नों के मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT-1176/67]

(ग) चालू मौसम में अब तक लगभग 36 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की गई है, और अधिप्राप्ति खाद्यान्नों की उपलब्धि और अधिप्राप्ति करने के लिये राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयत्नों पर निर्भर करेगी ।

(घ) अधिप्राप्त खाद्यान्नों का वितरण एक निरन्तर चलने वाला काम है ।

Import of Foodgrains after the closure of the Suez Canal

*1366. **Shri P. Viswambharan:**
Shri Mangalathumadom:
Shri P. C. Adichan:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the alternate steps Government have taken to tide over the difficulties in the import of foodgrains consequent on the closure of the Suez Canal;

(b) whether Government have purchased additional foodgrains from Eastern Countries after the Suez closure and if so, the quantities of wheat and rice thus purchased with details of countries from which the purchases were made; and

(c) whether these additional foodgrains have started arriving at the Indian ports?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The immediate impact of the closure of the Suez Canal with effect from the 6th June, 1967 has been on the food vessels which were on the high seas on that date and were to come to Indian ports *via* the Suez Canal. The delay involved in the arrival of these vessels consequent on their re-routing *via* the Cape of Good Hope has affected the availabilities of foodgrains during the second half of the month of June and the first half of the month of July. There was no possibility of meeting these shortfalls from any source during this period because of the time factor. The closure of the Suez Canal has also adversely affected the availability of tankers for foodgrains and in order to meet any deficiencies in supplies of imported grains during the months of July and August, commercial purchases of foodgrains have been made from Australia: Possibilities of diversion of foodgrain vessels from Australia to other places have also been explored but without any definite results so far.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shortage of Rice

*1367. **Shri Eswara Reddy:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the extent of shortage of rice in the country; and

(b) the steps which have been taken by Government to make the country self-sufficient in the matter of rice production?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) In the absence of any scientific and comprehensive survey on the consumption of foodgrains in India it is not possible to indicate the requirements and shortage of even all foodgrains taken together. The demand for one foodgrain competes against that of another to a certain extent. It is, therefore much more difficult to assess the extent of shortage of any particular foodgrain separately.